बजट 2020–21 की मुख्य बातें

बजट अनुमान 2020–21

❖ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का प्रस्तावित बजट - 65,000 करोड़ रुपये

स्कीम, कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए बजट	-	29,500 करोड़ रुपये
स्थापना बजट	-	35,500 करोड़ रुपये
राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बजट	-	48,070 करोड़ रुपये
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत बजट	-	16,930 करोड़ रुपये

❖ 2020–21 में बजट अनुमान 65,000 करोड़ है, जो 2019–20 के 60,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 8.33 प्रतिशत और 54,800 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 18.61 प्रतिशत अधिक है।

❖ 2020–21 में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 6,828 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2019–20 के बजट अनुमान में 6,380 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी। स्थानीय निकायों को कुल वित्तीय सहायता में 2299 करोड़ रुपये कर वसूली में हिस्सेदारी और 1805 करोड़ रुपये स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क तथा एकबारगी पार्किंग प्रभार आदि से संबंधित हैं। विभिन्न विकासात्मक स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 2020–21 में हम स्थानीय निकायो को 2724 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

❖ दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2019–20 के दौरान 10.48 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 7,74,870 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,56,112 करोड़ रुपये हो जाएगा।

❖ स्थिर कीमतों पर, दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2019–20 में 7.42 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो अखिल भारतीय विकास दर 5.0 प्रतिशत से बहुत अधिक है। पिछले पांच वर्षों में जीएसडीपी की वार्षिक औसत विकास दर 8.18 प्रतिशत रही है, जो दिल्ली की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को इंगित करती है।

❖ दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019–20 में 3,89,143 रुपये होने का अनुमान है, जो 2018–19 की प्रति व्यक्ति आय 3,58,430 रुपये के मुकाबले 8.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2015–16 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2,70,261 थी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय 2019–20 में 1,34,432 रुपये होने का अनुमान है।

❖ राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली का योगदान 2014–15 के 3.97 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 4.20 प्रतिशत हो गया, जबकि देश की कुल आबादी में दिल्ली का योगदान केवल 1.49 प्रतिशत है।

❖ बजटीय साधनों के माध्यम से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय 2015–16 के 19,004 रुपये से बढ़कर 2020–21 में 31,841 रुपये हो गया।

शिक्षा

❖ दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल 'केजरीवाल शासन के मॉडल का आधार है, जो सभी बच्चों को गुणवत्तापूण शिक्षा की गारंटी देता है, जिसमें सरकार कुल बजट का एक चौथाई भाग निरंतर शिक्षा पर खर्च कर रही है।

❖ शिक्षा क्षेत्र के लिए 2020–21 में भी सबसे अधिक 15,815 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो कुल बजट का 24.33 प्रतिशत है।

❖ सरकार ने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के उद्देश्य से कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, स्पोकन इंग्लिश, देशभक्ति पाठ्यक्रम आदि कई उपाय प्रस्तावित किए हैं।

❖ सरकार ने अपने सभी स्कूलों के क्लासरूमों को हाई–टेक डिजिटल क्लासरूमों में अपग्रेड करने की योजना बनायी है, जिसके अंतर्गत 9वीं से 12 वीं तक के सभी क्लासरूमों को हाई–टेक डिजिटल क्लासरूमों में परिवर्तित किया जाएगा।

❖ अगले वर्ष से स्कूल स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी और विद्यार्थियों को बहुप्रयोजनीय पहचान पत्रक प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा।

❖ अभिभावकों के ज्ञान और दक्षताओं के सकारात्मक विकास के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता दोनों के लिए विशेष अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

❖ सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण और उत्कृष्ट पाठ्यक्रम के विकास के लिए सरकार विभिन्न देशों के सर्वोत्तम मॉडलों और नए प्रयोगों का अनुकरण करेगी।

❖ सरकार दिल्ली का अपना राज्य शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगी। इसका प्रयोजन यह है कि शिक्षा में रट्टा पद्धति से अंक हासिल करने की बजाय विद्याथियों की समझबूझ बढ़ाने और सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके ताकि उन्हें विश्व की भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

❖ सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के समग्र विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बचपन में गुणवत्तापूर्ण ि"ाक्षा सुनि"चत करने के लिए एक नया कानून लायेगी।

❖ मौजूदा संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विस्तार और नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में समान और सस्ती शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य

❖ दिल्ली सरकार ने हर स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम किया और दुनिया भर से दिल्ली आने वाले भारतीयों को युद्धस्तर पर आइसोले"ान सुविधाएं उपलब्ध कराई। 2020–21 के लिए सं"ोधित अनुमान में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

❖ सरकार दिल्ली के नागरिकों को 451 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 24 पॉलीक्लिनिक्स और 36 मल्टी–स्पेशिएलिटी/सुपर–स्पेशलिटी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रही है। मौजूदा औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से 94 पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या भी बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। 2020–21 में स्थापित किए गए मोहल्ला क्लीनिकों और पॉलीक्लिनिकों के लिए 365 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

❖ सरकार ने बिस्तरों की क्षमता 10,000 से बढ़ाकर 26,000 करने के लिए मौजूदा अस्पतालों के उन्नयन और विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण का काम शुरू किया है। नए अस्पतालों के निर्माण और 16 मौजूदा सरकारी अस्पतालों के उन्नयन के लिए 2020–21 में 724 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

❖ दिल्ली में आरोग्य कोष के माध्यम से दी जा रही निःशुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, नैदानिक योजनाएं और चिकित्सा उपचार अब "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना" के दायरे में आएंगे। 2020–21 में "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना" के लिए 125 करोड़ रुपये और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

❖ दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में 2020–21 तक लागू करेगी, ताकि प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

❖ वरिष्ठ नागरिकों, संकट में फंसी महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजनाओं के लगभग 8.12 लाख लाभार्थियों के लिए 2020–21 में 2520 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

❖ समाज में व्यवहार परिवर्तन को गति देने संबंधी जागरूकता अभियान के लिए एक नई योजना 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवहार परिवर्तन' 2020–21 में शुरू की जाएगी।

❖ दिव्यांगजनों के तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना' और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक नई योजना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना प्रस्तावित है।

❖ दिल्ली के स्कूलों से 10 वीं और 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए भी मौजूदा योजना 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना' का विस्तार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समान करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

आवास और शहरी विकास

❖ सरकार अनधिकृत कालोनियों में जीवन की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए विकास कार्य फास्ट ट्रैक मोड में शुरू किया गया है। दिल्ली की 1797 अनिधिकृत कालोनियों में से 1281 में विकास कार्य पूरा हो चुका है/चल रहा है। सभी कालोनियों में विकास कार्य 2020–21 तक पूरा हो जाएगा।

❖ सामान्य विकास कार्य को स्थानीय स्तर पर पूरा कराने और इसमें कमियों को दूर करने के लिए 2020–21 के बजट में 400 करोड़ रुपये के परिव्यय से ''मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास'' नाम की एक नयी योजना का प्रस्ताव है। इसके अलावा ''मुख्यमंत्री सड़क पुनरोत्थान योजना'' के लिए 450 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। दिल्ली के हर गली कूचे में रहने वालों की सुरक्षा के लिए 2020–21 में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नयी योजना ''मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना'' का प्रस्ताव किया गया है।

❖ सरकार ने " मुख्यमंत्री आवास योजना " को अधिसूचित किया है जिसके तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए ''जहां झुग्गी वहां मकान'' योजना के अंतर्गत पक्के मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है।

❖ सरकार प्रत्येक झुग्गी बस्ती का विकास करने का प्रयास करेगी और उसमें रहने वालों को साफ–सुथरा व स्वच्छ माहौल उपलब्ध करायेगी और अंधेरी जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था करेगी और झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में बिजली वितरण कंपनियों के जरिए वर्तमान स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव कर उसे और बेहतर बनाया जाएगा।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

❖ सरकार ने अपने गारंटी कार्ड में दिये गये आश्वासनों के अनुसार कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। अगले पांच वर्षों में दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक परिवा को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना भी जारी रखी जाएगी।

❖ दिल्ली की अधिकतर अनधिकृत कालोनियों को पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इनमें से 1,549 कालोनियों में पानी की आपूर्ति पहले ही शुरू कर दी गयी है। बाकी 56 कालोनियों में पानी की आपूर्ति शुरू करने के लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

❖ 434 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछा दी गयी हैं। 597 कालोनियों में यह कार्य प्रगति पर है और इसके दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

❖ दिल्ली जल बोर्ड ने ''मुख्मंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना'' शुरू की है। यह योजना उन इलाकों के लिए जहां सीवर लाइनें तो हैं मगर लोगों ने अपने घरों के लिए कनेक्शन नहीं लिये हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और स्थापना शुल्क, प्रारंभिक शुल्क, सीवर कनेक्शन के लिए सड़क खुदाई के बाद उसे ठीक करने का शुल्क और सीवर आवेदन फार्म की लागत का भुगतान दिल्ली जलबोर्ड करेगा।

सड़कों का बुनियादी ढांचा

❖ दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 पर रामपुरा, त्रिनगर/इंदरलोक और कर्मपुरा पुल को चौड़ा करने का कार्य 20 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है और समूची परियोजना 2020–21 में पूरी कर ली जाएगी।

❖ करीब 1.32 लाख सीसीटीवी कैमररा पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और अब सरकार ने निवास कल्याण एसोसिएशनों और बाजार एसोसिएशनों के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की कुल संख्या 1.4 लाख से बढ़ाकर 2.8 लाख कर दी है। द्वितीय चरण में अतिरिक्त 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और यह 2020–21 में पूरा हो जाएगा।

❖ सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर सभी स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर बिजली की कम खपत करने वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाएगी जिससे स्ट्रीट लाइटों के संचालन के खर्च में कमी लाई जा सके।

❖ सरकार दिल्ली में 11,000 स्थानों पर वाइ–फाइ हॉटस्पॉट बनाकर आम आदमी को वाइ–फाइ सुविधा उपलब्ध करोने को वचनबद्ध है। यह कार्य शुरू कर दिया गया है और 2000 हॉट–स्पॉट बनाए भी जा चुके हैं।

परिवहन

❖ 'शासन संचालन के केजरीवाल मॉडल' के अतर्गत मुख्यमंत्री ने दिल्ली के निवासियों को सबसे बड़ी और सबसे किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की गारंटी दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने कुल 11,000 बसों का बेड़ा बनाने और 500 कि.मी. लंबी मेट्रो लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा है।

❖ लगभग 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में नई बसें जोड़ी गई हैं। बसें आधुनिक सीसीटीवी और 'दिव्यांगों के लिए अनुकूल लिफ्ट' से सुसज्जित हैं।

❖ दिल्लो के परिवहन बेड में नयी लो फ्लोर बसें राष्ट्रमंडल खेलों के बाद शामिल की गयी हैं। वर्ष 2020–21 में कुल मिलाकर 2,485 नयी बसें (1,300 डीटीसी और 1,185 क्लस्टर बसें) बेड़े में शामिल की जाएंगी जिनमें से 685 बिजली चालित बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा 1,880 बसें (444 डीटीसी और 1,436 क्लस्टर बसें) 2021–22 में शामिल की जाएंगी।

❖ ओखला, हरिनगर, वसंत विहार और हसनपुर समेत चार बस डिपो को मल्टीमोडल बस डिपो में बदलने का फैसला किया गया है। ये देश में संभवतया पहले मल्टीमोडल बस डिपो होंगे।

❖ महिलाओं की आर्थिक सक्षमता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अक्तूबर 2019 से उन्हें डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह योजना अगले साल भी जारी रहेगी।

❖ डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी निगरानी प्रणालो, और आपातकालीन सहायता हेतु पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे।

❖ दिल्ली मैट्रो के तृतीय चरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके विस्तार की योजना के तहत लाइनों के 158 कि.मी. विस्तार का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और उसपर ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इस चरण के करीब 2 कि.मी. खंड के निर्माण का कार्य इसी वित्त वष में पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने मैट्रो के चतुर्थ चरण की परियोजना के सभी छह कॉरीडोरों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लेकिन भारत सरकार ने चौथे चरण के छह गलियारों में से प्राथमिकता वाले तीन कॉरीडारों जनकपुरी–आर.के.आश्रम; एयरोसिटी–तुगलकाबाद आर मुकुदपुर–मौजपुर पैकेजों को ही मंजूरी दी है।

❖ दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत चालित वाहन नीति को 2019 में मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों की जगह बिजली से चलने वाले नये वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है ताकि परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी लाकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारा जा सके।

पर्यटन

❖ 'ब्रांडिंग डेल्ही' नाम की एक नयी योजना शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य दिल्ली आने वाले पर्यटकों को औसतन कम से कम दो दिन यहां बिताने को प्रोत्साहित करना है। उनके सिर्फ एक दिन के लिए यहां ठहरने से दिल्ली में रोजगार के लाखों नये अवसर उत्पन्न होंगे और अर्थव्यवस्था के विकास के नये मौके बढ़ेंगे।

❖ लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, 'सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अभियान' की एक नई योजना भी शुरू की गई है।

पर्यावरण और वन

❖ दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाए रखना दिल्ली को हराभरा बनाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वासियों को दी गयी 10 गारंटियों में से एक है। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा में योगदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए हरित नागरिक पुरस्कार शुरू किये जाएंगे।

❖ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर अमल सुनिश्चित करने के लिए 2020–21 में 2 करोड़ रुपये के परिव्यय से ''मार्शलों की तैनाती'' की एक नयी योजना शुरू की जाएगी।

❖ ''प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन''योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर फैले हवा का प्रदूषण दूर करने के लिए स्मॉग टॉवर स्थापित किए जाएंगे।

❖ अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ पौधे रोपने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 22 हरित एजेंसियों ने 2020–21 में 40 लाख पौधे लगाने का बीड़ा उठाया है।

ऊर्जा

❖ सरकार ने महीने में 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए उनके स्वीकृत लोड का ध्यान रखे बिना बिजली शुल्क माफ करने की 'ज़ीरो पावर बिल' योजना शुरू की है। इसके अलावा 201 से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में 800 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्लो में करीब 90 प्रतिशत परिवारों को बिजली बिल में सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा सरकार सिक्खों के खिलाफ 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की 400 यूनिट खपत करने पर बिजली बिल में शत प्रतिशत सब्सिडी दे रही हं। ये योजनाऐं अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेंगी।

❖ सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले लोगों/संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थाओं और अदालतों आदि में सौर विद्युत संस्थान स्थापित करने की प्रकिया जारी है। ''मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना'' के अंतर्गत सौर किसानों ने बिजली घर लगाने के लिए करीब 200 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है।

❖ बिजली वितरण कंपनियां दिल्ली का विभिन्न भागों में फैले बिजली के उलझे हुए तारों के जंजाल स अगले पांच साल में मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करेंगी ताकि जान–माल के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और शहर भी खूबसूरत बने।

''''''